RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : गुरुवार 28 जुलाई 2022 वर्ष 04 अंक 89 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

औरंगाबाद का नाम बदलने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ

बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

मुंबई : औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। औरंगाबाद के निवासी मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अन्नासाहेब खंडारे और राजेश मोरे द्वारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालय एक अगस्त को सुनवाई कर सकता है।

राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार ने इस साल 29 जून को आखिरी कैबिनेट बैठक में शहर का नाम संभाजीनगर करने का फैसला किया था। वहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नयी सरकार ने इस महीने की शुरूआत में एक नया प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मराठवाड़ा क्षेत्र के सबसे बड़े शहर का नाम ह्यछत्रपति संभाजीनगर रखे जाने को मंजूरी दी गई। याचिका में दावा किया गया है कि 2001 में राज्य सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलने का प्रयास किया था लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया था। याचिका में दावा किया गया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने ''राजनीतिक कारणों से अपने अंतिम समय पर अनधिकृत रूप से औरंगाबाद का नाम बदलने का मुद्दा पिछली कैबिनेट बैठक में उठाया था। याचिका में आगे कहा गया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखे बिना और संविधान के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए इस फैसले को बरकरार रखा।

मुंबई में सेक्सटोर्शन!

सोशल मीडिया से फोटो उठाकर, महिलाओं के फोटो की बनाता था क्लिप

फिर करता था ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल

मुंबई : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 19 वर्षीय लड़का पहले सोशल मीडिया से महिलाओं की फोटो लेता था जिसके बाद उन्हें एडिटिंग के बाद गंदी वीडियो में तब्दील कर देता था। जिसके बाद आरोपी ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू करता था। आरोपी महिलाओं से फोटो डिलीट करने के लिए 500 रुपयों से लेकर 4 हजार रुपयों तक की डिमांड कर देता था। अगर कोई पेमेंट में देरी करता था तो आरोपी अपना चार्ज बढ़ा देता था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को उसके घर गांधीनगर गुजरात से गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि, आरोपी दसवीं क्लास में फेल होने के बाद से पढ़ाई नहीं कर रहा था। जिसके बाद उसने एक मास्क बनाने वाली फर्म में काम करना शुरू किया। खास बात है कि, आरोपी ने सिर्फ उसी की कम्युनिटी की महिलाओं को टारगेट किया और फोटो की मदद से गंदी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल शुरू किया है। अभी तक 22 महिलाओं का मामला सामने आ चुका है। हालांकि, पुलिस का मानना है कि, आरोपी अभी तक 49 महिलाओं को अपने निशाने पर ले चुका लेकिन इसकी पुष्टि के लिए अभी पुलिस आगे जांच कर रही है।

आरोपी जब महिलाओं से पेमेंट लेता तो वह उन्हें एक क्यूआर कोड भेजता था। ये क्यूआर कोड गुजरात में चल रही एक ट्रैवल एजेंसी का था। ट्रैवल एजेंसी में आरोपी ने बताया था कि, उसका बैंक अकाउंट नहीं है, इसलिए वह अपनी कमाई का पैसा इसके जरिए मंगा रहा है। हालांकि, ट्रैवल एजेंसी उसे अपना क्यू आर कोड इस्तेमाल करवाने के बदले 50 रुपये हर बार लेती थी। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल भी जब्त कर लिया है जिसे जांच के लिए भेजा गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि, किसी ने उसके साथ भी ऐसा ही किया था, जिसके बाद से वह औरों से अपना बदला ले रहा है।

महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक का सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र

सड़कों में गड्ढे को लेकर दी शिकायत

मुंबई : मुंबई में हर साल बरसात के मौसम में सड़क तालाब में बदल जाती है और कई जगहों पर तो गड्ढे हो जाते हैं. वहां से गाड़ियां तो दूर की बात चलना भी मुश्किल हो जाता है. इसी संदर्भ में मुंबई में सड़कों की ऐसी हालत देख कर अब बीजेपी से विधायक अमित साटम ने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस को पत्र लिखकर शिकायत की और उनसे अनुरोध किया कि इसके लिए उचित योजना बनाई जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके. साटम ने अपने पत्र में कहा है की पिछले 24 साल में मुंबई की सड़कों पर महानगर पालिका की तरफ से 21,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं बावजूद इसके मुंबई में सड़कों की हालत जस की तस है. साटम ने 26 जुलाई को सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा था. साटम ने कहा कि मैं आपका ध्यान मुंबई की सड़कों और गड्ढों की समस्या पर लाना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि ये समस्या दूरदर्शिता और सोच की कमी के कारण हल नहीं हुई.

असंगठित फेरीवालों की समस्या पर भी डाला प्रकाश

साटम ने मुंबई में असंगठित फेरीवालों की समस्या पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि यहां पर हॉकर्स का मुद्दा अजीब हो गया है और इसे विनियमित करने की जरूरत है. जोनल टाउन वेंडिंग कमेटियों ने हॉकिंग जोन की पहचान की और 1.28 लाख फेरीवालों को हॉकिंग पिचों के आवंटन का पात्र बनाया. हालांकि पिछली सरकार ने नासमझी से 2019 के सर्वेक्षण के पूरा होने तक प्रक्रिया को निर्लंबित कर दिया.

फुटपाथ और सड़कों को किया जाये साफ

साटम ने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि निर्दिष्ट हॉकिंग जोन में हॉकिंग पिचों को पात्र हॉकरों को दें और हमारी शेष सड़कों और फुटपाथों को साफ करें. साटम ने भरोसा जताया कि ऐसी दो समस्याओं का तार्किक निष्कर्ष शहर के लंबे समय से लंबित मुद्दों को सफलतापूर्वक हल करने में मदद करेगा.

पंजाब से गिरफ्तार आरोपी,

मुंबई हवाई अड्डे से फरार...

मुंबई : पंजाब से गिरफ्तार कर मुंबई लाया जा रहा 25 वर्षीय आरोपी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान सागर मसीह के रूप में की है। पवई पुलिस ने भगोड़े आरोपी के खिलाफ सहार पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 224 के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी है, अब पवई पुलिस के साथ-साथ सहार पुलिस भी सागर की तलाश कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, सागर मसीह का एक दोस्त व्यापारी है और उसका दूसरे व्यापारी से बिजनेस संबंधित पैसा बकाया था। उसकी लेन-देन को लेकर शिकायतकर्ता व्यापारी ने सागर के दोस्त के खिलाफ मारपीट और रॉबरी का केस दर्ज कराया था,जिसमे सागर का भी नाम था। इसी सिलसिले में पवई पुलिस सागर को पंजाब के गुरदासपुर से गिरफ्तार कर मुंबई ला रही थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जो टीम सागर को मुंबई ला रही थी उनकी फ्लाइट रविवार की सुबह 11.30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी और उसके बाद हवाई अड्डे पर भीड़ का फायदा उठाकर सागर पुलिस को चकमा देते हुए भाग गया है।

संपादकीय / लेख

आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, यह बताने के लिए किसी का अर्थशास्त्री होना जरूरी नहीं है। अगर राजनीतिक झुकावों को एक तरफ भी रख दें, तब भी सच यही है कि बीते पांच सालों से अर्थव्यवस्था खस्ताहाल बनी हुई है। अगर मैक्रो-इकोनॉमिक संकेतकों को देखें तो वे कोई रुपहली तस्वीर नहीं पेश करते। रीटेल महंगाई जून में 7.01% थी। यह बीते 33 महीनों से आरबीआई के 4% के मध्यावधि लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। वहीं 6% की अधिकतम सीमा से भी विगत छह माह से वह अधिक है। बेरोजगारी दर लगातार 7.5% से अधिक बनी हुई है। सीएमआईई के मुताबिक अकेले जून में 25 लाख लोगों ने नौकरियां गंवाईं। इस सबसे बढ़कर है रुपए में गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया छह महीनों में लगभग 7% तक गिरा है। बीते कुछ दिनों में वह कुछ बार 80 के मनोवैज्ञानिक बैरियर को भी लांघ चुका है। भारत जैसे देश के लिए उसकी मुद्रा का मूल्य घटना बड़ी समस्या है, क्योंकि हम मुख्यतया आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था हैं। हमारे द्वारा किया जाने वाला आयात हमारे निर्यात से अधिक है। आयात-निर्यात के इस असंतुलन से निर्मित होने वाला चालू खाता घाटा इस वित्त वर्ष में जीडीपी के 3.3% को पार कर सकता है। जब रुपया कमजोर होता है तो आयात का बिल तो बढ़ता है, निर्यात भी प्रभावित होता है। विदेशी आयातकों को उसी डॉलर की राशि में भारतीय निर्यातकों से ज्यादा माल मिल जाता है। इसमें मुश्किल यह भी है कि हमारे निर्यात-श्रेणी में आने वाली मुख्य चीजें जैसे ज्वेलरी, कीमती रत्न, पेट्रोलियम उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल आदि का भी कच्चा माल बड़े पैमाने पर आयात किया जा रहा है, जिस कारण कमजोर मुद्रा से निर्यात में होने वाला लाभ कम हो जाता है। घरेलू महंगाई टेक्सटाइल जैसे श्रम-सघन निर्यातों के अपेक्षित लाभ को भी कम कर देती है। चिंता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है विदेशों के डॉलर बाजारों से ऋण लेना। दिसम्बर 2021 के अंत में कॉमर्शियल कर्जदारी 226 अरब डॉलर की थी। इसमें ब्याज के भुगतान को जोड़ दें तो आप पाएंगे कि सरकारी खजाने को लगने वाली चपत से सरकार की पूंजी या व्यय बढ़ाने की क्षमता और प्रभावित होगी। तीसरा कारण है विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजारों से पैसा निकाल लेना। विदेशी संस्थानगत निवेशकों ने इस साल 28.4 अरब डॉलर के शेयर बेचे हैं। इसकी तुलना 2008 के वैश्विक संकट से करें तो तब मात्र 11.8 अरब डॉलर के ही शेयर बेचे गए थे। आरओबाई के मुताबिक जब रुपए में 5% गिरावट आती है तो मुद्रास्फीति 0.15% बढ़ जाती है। जो अर्थव्यवस्था पहले ही उच्च मुद्रास्फीति से परेशान हो, वह रुपए की ज्यादा गिरावट सहन नहीं कर सकती। उच्च मुद्रास्फीति के लिए केवल वैश्विक संकट जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि आरबीआई को मुद्रास्फीति कम करने के लिए मौद्रिक नीति के उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, वहीं केंद्र सरकार को कर्ज नियंत्रित करना चाहिए। आरबीआई पहले ही आक्रामक रूप से ब्याज दरें नहीं बढ़ाकर मौका गंवा चुका है। जबकि अमेरिका का केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए यही कर रहा है। दूसरे, हमें प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट होना चाहिए कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण जरूरी है या विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन? ये सच है कि बीते नौ महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार 70 अरब डॉलर घटकर 20 महीनों के निम्नतम स्तर 572 अरब डॉलर पर चला गया है, इसके बावजूद हमारी प्राथमिकता महंगाई के उन कारणों पर अंकुश लगाना ही होना चाहिए, जिनके लिए वैश्विक परिस्थितियां ही जिम्मेदार नहीं हैं।

editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

उमेश कोल्हे मर्डर के आरोपी शाहरुख पठान पर हमला, मुंबई की आर्थर रोड जेल में 5 कैदियों ने किया अटैक

मुंबई बाकी आर्थर रोड जेल में आरोपी शाहरुख पठान पर जानलेवा हमला

शाहरुख पठान उमेश कोल्हे हत्याकांड का एक आरोपी है

मुंबईः आर्थर रोड जेल में एक बार फिर से एक आरोपी पर जानलेवा हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शाहरुख पठान के ऊपर पांच कैदियों ने हमला किया है। आपको बता दें कि शाहरुख पठान को महाराष्ट्र के मेडिकल व्यवसाई उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उसे एनआईए ने गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने शुरू की जांच

आरोपी शाहरुख पठान के ऊपर हमले के बाद मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। शाहरुख की बैरक में रहने वाले अन्य आरोपियों ने ही उस पर जानलेवा हमला किया है। फिलहाल आरोपियों को अलग-अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है।

महाराष्ट्र के अमरावती जिले में रहने वाले मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्हे की बीजेपी की नूपुर शर्मा का समर्थन करने की वजह से हत्या कर दी गई थी। जब उसने यह बात बैरक में मौजूद अन्य कैदियों को बताई। तब बैरक में मौजूद कैदी कल्पेश पटेल, हेमंत मनेरिया, अरविंद यादव, श्रावण आडव और संदीप जाधव ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। शाहरुख पठान आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर सात में बंद था।

पीसीएस इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा, अटाला मस्जिद किसने बनवाई ऐतिहासिक महत्व बताइए?

मुंबई, सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) 2021 भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चल रहे साक्षात्कार के चौथे दिन सोमवार को इंटरव्यू बोर्ड ने अभ्यर्थियों से समसामयिक प्रश्न पूछने के साथ ही उनकी तार्किक क्षमता का भी आकलन किया। एक अभ्यर्थी से 'पिछले महीने प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल से जोड़कर प्रश्न पूछा-'अटाला मस्जिद किसने बनवाई, ऐतिहासिक महत्व बताइए?'

एक अभ्यर्थी से पूछा-'मुख्यमंत्री कहते हैं कि योजना का लाभ निचले स्तर तक पहुंच रहा है। ये निचला स्तर क्या है?' एमएसपी के तहत गेहूं की सबसे ज्यादा खरीद उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुई है?, ऋषि सुनक यदि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?, क्या उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांट देना चाहिए? यदि हां तो क्यों, यदि न तो क्यों?, ड़िफेंस कॉरिडोर कौन-कौन से शहर से गुजर रहा है? और उत्तर प्रदेश प्रशासन की कोई दो कमियां बताइए? हिमखंड क्यों पिघल रहा है? इसके बचाव में सरकार क्या कदम उठा रही है? और धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है? जैसे प्रश्नों ने चौंकाया।

कई प्रश्न अभ्यर्थियों के निर्णय क्षमता को परखने के लिए किए गए। एक महिला अभ्यर्थी से बोर्ड ने पूछा-'आप किसी जिले में एसडीएम हैं और मुख्यमंत्री का आपके क्षेत्र में दौरा है। आपको जाना है और आपका बच्चा बहुत बीमार है। इस स्थिति से आप कैसे निपटेंगी?, आप महिला हैं क्या आपने घर, रिश्तेदार, समाज, स्कूल में अपने प्रति कभी भेदभाव महसूस किया है?, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो आप सोशल सर्विस क्यों करना चाहती हैं? क्या सोशल सर्विस के लिए एसडीएम बनना जरूरी है?, आप एसडीएम क्यों बनना चाहती हैं, जबकि आप खुद कोषाधिकारी हैं?, आप दिल्ली में रहीं है, क्या आपने दिल्ली में सुरक्षा महसूस की है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को लेकर आपके क्या विचार हैं?

ED को गिरफ्तारी का अधिकार, मनी लॉन्ड्रिंग कानून में बदलाव सही; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

मुंबईः प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारों और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है।

अदालत ने कहा है कि ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार है। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है, ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट में कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और ढटछअ को लेकर दायर 240 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट में जो बदलाव किए गए थे, वह सही हैं। यही नहीं कोर्ट ने कहा कि एजेंसी की ओर से गिरफ्तारी करना और आरोपियों से पूछताछ करने में कुछ भी गलत नहीं है।

हालांकि शीर्ष अदालत ने यह जरूर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत जमानत के नियमों में थोड़ी ढील होनी चाहिए। याचिकाकताओं की एक और मांग पर अदालत ने कहा कि ईडी ने कोई शिकायत दर्ज की है तो उसकी कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं है। इसके अलावा सीबीआई या अन्य किसी एजेंसी की ओर से बंद किए गए मामले को भी ईडी अपने हाथ में लेकर जांच कर सकती है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट में मनी बिल के तहत बदलाव किए जाने के सवाल को अदालत ने 7 जजों की बेंच के सामने भेजने का फैसला लिया है। दायर की गई याचिकाओं में ईडी की ओर से रेड, गिरफ्तारी के अधिकारी, संपत्ति को जब्ध करने और बेल की कठिन शर्तों पर विचार करने की अपील की गई थी।

‘आदिपुरुष’ बनेगी भारतीय सिनेमा की नई पहचान

निर्देशक ओम राउत की मेहनत को मेरा प्रणाम

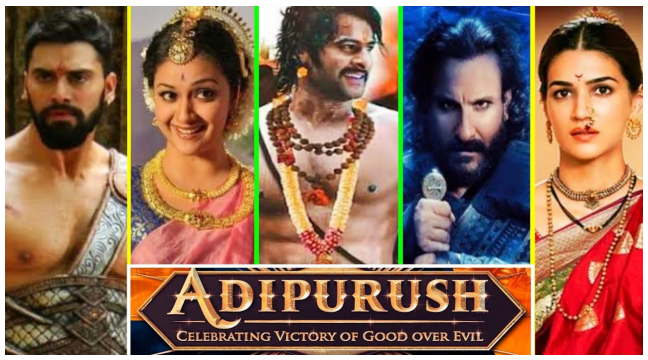

मुंबई, हिंदी सिनेमा में इन दिनों अगर किसी एक अभिनेत्री के पास विविधतापूर्ण किरदारों का पूरा गुलदस्ता है तो उनमें कृति सेनन का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी आने वाली फिल्में ‘आदिपुरुष’, ‘भेड़िया’, ‘गणपत’ और ‘शहजादा’ से भी उनके चाहने वालों को काफी उम्मीदें हैं। पराक्रमी राम पर बन रही उनकी फिल्म ‘आदिपुरुष’ उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म है और इसका इंतजार सिर्फ भारतीय दर्शक ही नहीं बल्कि भारतीय मूल के वे करोड़ों दर्शक भी कर रहे हैं जो दुनिया के तमाम दूसरे देशों में रह रहे हैं। करीब 20 हजार स्क्रीन्स पर इसे रिलीज करने की तैयारी है और कृति को पता है कि ये फिल्म उनके लिए कितनी अहम है। कृति सेनन कहती हैं, ‘फिल्म ‘आदिपुरुष’ हम सबके लिए खास फिल्म है और इसमें सीता का किरदार बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसा किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। फिल्म के निर्देशक ओम राउत ने इस फिल्म को जिस तरह से तैयार किया है, वह किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उनकी मेहनत को मैं प्रणाम करती हूं। उन्होंने इस फिल्म में सीता की जो छवि गढ़ी है, वह अब तक छोटे परदे या फिल्मों में दिखी उनकी छवियों से काफी अलग है। मुझे पूरा यकीन है कि फिल्म ‘आदिपुरुष’ भारतीय सिनेमा की एक नई पहचान बनकर उभरेगी।’

कृति की पिछली दो फिल्में ‘बच्चन पांडे’ और ‘हम दो हमारे दो’ खास कमाल नहीं कर पाईं। लेकिन, इन दोनों फिल्मों में कृति ने अपने किरदार को लेकर काफी मेहनत की। वह कहती हैं, ‘फिल्म का बॉक्स ऑफिस नतीजा क्या होगा, ये तो फिल्म बनाते समय किसी को नहीं पता होता। हमारे बस में होता है हर फिल्म के लिए अपना सौ फीसदी समर्पण दिखाना। किसी भी किरदार को करने के लिए, उसको जीने के लिए जो कुछ भी जरूरी होता है। मैं करती हूं।’

बचपन से ही माधुरी दीक्षित की दीवानी रहीं कृति सेनन पेशे से इंजीनियर रही हैं। पिता राहुल सेनन सीए हैं और मां फिजिक्स की प्रोफेसर। बहन नुपूर का भी मॉडलिंग और एक्टिंग में खासा नाम है। निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की फिल्म ‘पानीपत’ को कृति अपने करियर का टर्निंग प्वाइंट मानती हैं। वह कहती हैं, ‘पानीपत की लड़ाई पर आधारित एक फिल्म मे अगर एक युवती का किरदार उभर कर आ जाए तो वही अपने आप में बड़ी बात है। युद्ध आधारित फिल्मों में अक्सर ऐसा होता नहीं है लेकिन फिल्म ‘पानीपत’ में ऐसा हुआ। एक अभिनेत्री के तौर पर मुझे लगता है कि मुझे वहां बहुत सराहा गया और इसके बाद ही मुझे खुद भी अंदर से महसूस हुआ कि मैं अब इससे भी चुनौतीपूर्ण कुछ कर सकती हूं।’

फिल्म ‘मिमी’ के लिए दर्जनों पुरस्कार जीत चुकीं कृति सेनन इस फिल्म के बारे में चर्चा चलने पर कहती हैं, ‘कहीं न कहीं मैं ढूंढ रही थी ऐसा कोई किरदार। कई बार हम अंदर से किसी काम को करने के लिए तैयार होते हैं और आपको वही करने का मौका मिल जाता है। ‘लुकाछिपी’ में काम करने के चलते ही मुझे ये फिल्म मिली थी। ‘लुकाछिपी’ हालांकि बहुत ही हल्की फुल्की फिल्म थी जबकि ‘मिमी’ बहुत ही भावुक फिल्म है। ‘लुकाछिपी’ में एक बहुत ही इमोशनल सीन था, जिसे देखने के बाद मुझे ‘मिमी’ का चुनौतीपूर्ण रोल सौंपा गया।’

अजीत पवार ने सीएम शिंदे के दिल्ली दौरे की आलोचना की; शिंदे ने कहा...

मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आज हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने शिंदे सरकार के दिल्ली के कदम की भी आलोचना की। मुख्यमंत्री शिंदे आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज उनका दिल्ली का छठा दौरा होगा। अजित पवार ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान दिल्ली में सारे फैसले लिए गए। दिल्ली में भी बीजेपी सरकार के फैसले होते हैं। एनसीपी के फैसले मुंबई में होते हैं। शरद पवार मुंबई में हैं। मुंबई में उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में फैसले लिए गए। ममता बनर्जी के फैसले कोलकाता में होते हैं। पार्टी क्या मायने रखती है। अब शिंदे के फैसले दिल्ली में होते हैं, अजीत पवार ने उनसे पूछा कि वह क्या करेंगे।

मुंबई में स्वाइन फ्लू के मामलों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी

BMC ने हाई रिस्क ग्रुप वालों को दी ये सलाह

मुंबई, महानगर में स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा ल्ट1ठ1 का खतरा बढ़ता जा रहा है. पिछले दो सालों के मुकाबले इस साल शहर में स्वाइन फ्लू के मामलों में काफी इजाफा हुआ है.इसी को देखते हुए बीएमसी ने मंगलवार को हाई रिस्क ग्रुप वाले उन लोगों को जिनमें सांस फूलना और सीने में दर्द जैसे एडवांस लक्षण दिख रहे हैं उन्हें डॉक्टर की सलाह लेने और यहां तक कि अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा है.

मुंबई में इन्फ्लूएंजा ल्ट1ठ1 (पूर्व में स्वाइन फ्लू) के 66 मामलों की पुष्टि हुई है जो 2021 के 64 और 2020 के 44 केसों के आंकड़े को पार कर गए हैं. गौरतलब है कि स्वाइन फ्लू के मामलों में ये इजाफा जुलाई महीने में हुआ है, जिसमें अकेले इस महीने 66 मामलों में से 62 मामले दर्ज किए गए हैं. टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि आधिकारिक संख्या वास्तविक संख्या को नहीं दर्शा रही है. क्योंकि टेस्टिंग और रिपोर्टिंग दोनों लिमिटेड हैं. परेल के केईएम अस्पताल की डीन डॉ संगीता रावत ने कहा कि वे रोजाना एच1एन1 के लगभग पांच से छह पॉजिटिव मामले देख रहे हैं. वहीं हिंदुजा अस्पताल, खार में क्रिटिकल केयर के प्रमुख डॉ भारेश डेढिया के अनुसार, संक्रमण बढ़ रहा है. उन्होंने खुद पिछले कुछ हफ्तों में 30 लैब-कन्फर्म केस देखे हैं. उनमें से 7-8 गंभीर मामलों में फेफड़ों और अन्य जटिलताओं के शामिल होने के कारण अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी थी. चेस्ट फिजिशियन डॉ सुजीत राजन ने कहा कि शुरूआती दिनों में कोविड-19 और एच1एन1 के बीच अंतर करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

क्या करें और क्या न करें की लिस्ट बनाते हुए बीएमसी ने कहा कि एच1एन1 आमतौर पर बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, सिरदर्द, दस्त जैसे लक्षणों के साथ आता है, जो इलाज के बाद कम हो जाते हैं. कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी मंगला गोमारे ने कहा, ‘हालांकि, अगर हाई रिस्क ग्रुप वाले लोगों, जैसे कि गर्भवती महिलाएं या डायबीटिज या हाईपरटेंशन वाले लोगों में सांस फूलना, सीने में दर्द, उल्टी में खून, नाखूनों का नीला पड़ना जैसे अतिरिक्त लक्षण दिखते हैं तो उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है.’

वहीं डॉक्टरों के मुताबिक मामलें को ज्यादा पता इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि इसकी टेस्टिंग ज्यादातर सार्वजनिक अस्पतालों में नहीं है, और निजी क्षेत्र में परीक्षण की लागत 2,000-5,000 रुपये है. हालांकि कस्तूरबा अस्पताल में निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध है.

नवी मुंबई पुलिस के विभाग में शामिल हुआ दो महीने का Labrador Retriever

जल्द केस सुलाझने में करेगा मदद

नवी मुंबई, पुलिस डिपार्टमेंट में खोजी कुत्ते काफी अहम होते हैं. इन कुत्तों की मदद से पुलिस कई ब्लाइंड केस को सॉल्व कर चुकी है. यहीं वजह है कि पुलिस विभाग समय-समय पर अच्छी नस्ल के कुत्ते खरीदता रहता है और फिर उन्हें ट्रेंड किया जाता है. इसी कड़ी में नवी मुंबई पुलिस ने एक दो महीने का लैब्राडोर रिट्रीवर खरीदा है. इस कुत्ते को बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीडीएस) के लिए एक खोजी कुत्ते के रूप में ट्रेंड किया जाएगा.

नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त बिपिन कुमार सिंह ने पीले रंग के कुत्ते को ‘रैम्बो’ नाम दिया है. छह महीने का होते ही रेम्बो एक डॉग ट्रेनिंग सेंटर में विस्फोटकों को सूंघने का प्रशिक्षण लेगा. रेम्बो ने खोजी कुत्ते वीरू की जगह ली है. दरअसल वीरू की दिसंबर 2017 में मौत हो गई थी. वर्तमान में, इञ्ळ स्कवॉड में जैक और सिम्बा नाम के दो प्रशिक्षित लैब्राडोर हैं.बीडीडीएस के पुलिस निरीक्षक संतोष केन ने बताया कि चार पैरों वाला नया रंगरूट 4 मई को पैदा हुआ था और उसे एक पालतू जानवर की दुकान पर बेचा जा रहा था. लेकिन नवी मुंबई पुलिस ने इसे खरीद लिया और अब इसे खोजी कुत्ते के तौर पर तैयार किया जाएगा.

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : गुरुवार 28 जुलाई 2022

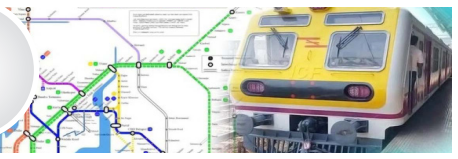

एसटी महामंडल की लापरवाही के कारण

भिवंडी स्थित बस स्टैंड परिसर पर गड्ढे ही गड्ढे

भिवंडी, एसटी स्टैंड गड्ढों से समूचा भर गया है। देखने में ऐसा लगता है कि बस स्टैंड बसों के लिए न होकर गड्ढों के लिए ही बनाया गया है। एसटी महामंडल की लापरवाही के कारण भिवंडी स्थित बस स्टैंड परिसर गड्ढों से पूर्णतया भर गया है। बसों पर चढ़ने के लिए प्रतिदिन हजारों यात्रियों, छात्र-छात्राओं को गड्ढों में जाकर ही यात्री बसों पर चढ़ना पड़ रहा है।

मजबूरी हो गयी है। क्षेत्रीय बस स्टैंड प्रबंधक से की जा रही बार-बार शिकायतों के बाद भी गड्ढों की भराई नहीं की जा रही है जिससे यात्रियों में भारी आक्रोश फैल रहा है। गौरतलब है कि बरसात से पहले ही भिवंडी बस स्टैंड परिसर में जानलेवा गड्ढों की भरमार थी जो बारिस में बृद्धि हो गयी है। एसटी स्टैंड परिसर गड्ढों से भरा पड़ा है जिससे गुजरकर ही यात्री बसों पर चढ़ना और उतरना प्रतिदिन हजारों यात्रियों की भारी मजबूरी बन गई है।

बस यात्री चढ़ते उतरते वक्त गड्ढों में गिरकर हाथ पाँव-तोड़ कर उपचार

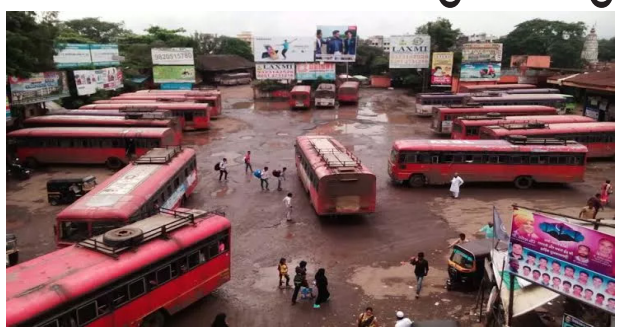

के लिए मजबूर हैं। यात्रियों ने बस स्टैंड प्रमुख पर लगाया ये आरोप भिवंडी पावरलूम नगरी होने की वजह से प्रतिदिन हजारों यात्री व्यापार के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों जैसे कल्याण, ठाणे, नवी मुंबई, नासिक, मुंबई, वाड़ा आदि दूरदराज क्षेत्रों को जाते और आते हैं।

यात्रियों ने बस स्टैंड प्रमुख की कार्यप्रणाली पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बताया कि एसटी महामंडल को प्रतिमाह भिवंडी से करोड़ों की आय होती है, बावजूद महामंडल बस स्टैंड के रखरखाव और सुरक्षा पर पाई भी खर्च नहीं करता दिखाई पड़ता है। बस स्टैंड परिसर में चहुंओर फैले भारी भरकम गड्ढों को भरे जाने के लिए महामंडल अधिकारी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। एसटी महामंडल अधिकारी कभी-कभार नाममात्र ही गड्ढों की भराई किया करते हैं जो घटिया सामाग्री होने के कारण अल्प समय में ही गड्ढे पुनः जस के तस हो जाते हैं।

राजस्व को करोड़ों का चूना : फर्जी चालान के आरोप में गिरफ्तार

मुंबई, महाराष्ट्र जीएसटी विभाग ने दो कर चोरों को गिरफ्तार किया है। ये जालसाज फर्जी खरीद चालान के जरिए कर की चोरी करते हुए सरकार के राजस्व को करोड़ों का चूना लगा रहे थे। इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पाकीजा स्टील कंपनी और मायल स्टील प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सैयद तौकीर हसन रिजवी समेत दो लोगों को इस मामले में 185 करोड़ रुपए के फर्जी चालान प्राप्त करने और जीएसटी भुगतान किए बिना 22 करोड़ रुपए की नकली कटौती प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र जीएसटी विभाग द्वारा की गई है।

सैयद तौकीर हसन रिजवी पाकीजा स्टील एलएलपी और मेसर्स मायल स्टील प्रा. लिमिटेड नामक दोनों फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 185 करोड़ रुपए के फर्जी खरीद

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य की विभिन्न इकाइयों को बड़ा तोहफा दिया

किसानों को 50 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य की विभिन्न इकाइयों को बड़ा तोहफा दिया है. शिंदे ने कहा है कि नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इस दौरान यह भी घोषणा की गई कि किसानों को बिजली दरों में रियायत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह पुलिस के आवास के लिए मास्टर प्लान तैयार करेंगे।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री के बड़े ऐलान अनुसूचित ऋण चुकौती करने वाले किसानों को 50 हजार रुपये की सब्सिडी 3 साल की अवधि घटाकर 2 साल कर दी गई लगभग 50 हजार किसानों को होगा सीधा लाभ एक घोषणा कि किसानों को बिजली दरों में रियायत दी जाएगी प्रति यूनिट 1 रुपये की छूट 2.16 पैसे के बजाय 1.16 पैसे पश्चिमी महाराष्ट्र के किसानों को सीधी मदद पैठण सिंचाई योजना की स्वीकृति भाटसा दामो के लिए 1550 करोड़ मंजूर 15 मेडिकल कॉलेजों में 50 सीटें बढ़ाने का फैसला लोनार सरोवर विकास योजना को मिली मंजूरी, 370 करोड़ मंजूर हल्दी अनुसंधान केंद्र की मंजूरी, 100 करोड़ रुपये का फंड संदीपन भुमरे के निर्वाचन क्षेत्र के 40 गांवों को होगा फायदा थाने का मास्टर प्लान बनेगा कोरोना काल के अपराधों की जांच कराकर वापस लिया जाएगा

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दिल्ली में बातचीत में व्यस्त, राज्य को अपंग करके छोड़ दिया - जयंत पाटील

मुंबई, गुवाहाटी प्रवास और मंत्रिमंडल शपथ से लेकर अब तक जोड़ा जाए तो दो महीने हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दिल्ली में बातचीत में व्यस्त हैं। उन्होंने राज्य को अपंग करके छोड़ दिया है। ऐसा आरोप पूर्व जल संसाधन मंत्री जयंत पाटील ने लगाया। एक सवाल का जवाब देते हुए जयंत पाटील ने शिंदे सरकार पर जमकर हमला बोला।

जयंत पाटील ने कहा कि राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि उनके बीच मतभेद हैं। जयंत पाटील ने यह भी कहा कि जो लोग अपनी प्रिय शिवसेना को छोड़कर गए हैं, वे वहां फल प्राप्ति तक शांत बैठेंगे, ऐसा नहीं दिखाई देता है। इस कारण उनमें मतभेद अधिक होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि राज्य में आज गरीबों की समस्या सुलझने के बजाय बढ़ने लगी है। राज्य में बारिश की स्थिति गंभीर है, बाढ़ के कारण सामान्य नागरिक परेशान है। उस क्षेत्र में पालकमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में राज्य में सिर्फ दो मंत्री हैं। ये दोनों मंत्री जनता की समस्या सुलझाने की जगह, अपनी समस्या को हल करने में अधिक समय बिता रहे हैं, ऐसी टिप्पणी जयंत पाटील ने की।

मनपा आयुक्त ने गणेश मंडलों को दिया आश्वासन

बाप्पा आगमन से पूर्व सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त

ठाणे, अगले महीने बाप्पा का आगमन होने जा रहा है। इस साल त्योहार पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, जिसे लेकर गणेश भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। गणेश उत्सव के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा का सामना गणेश भक्तों को न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद हो चुका है। यह कहते हुए मनपा आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा ने विश्वास जताया है कि प्रशासन की तरफ से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और इस बार गणेश उत्सव के दौरान सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी।

बता दें कि मंगलवार को मनपा मुख्यालय में गणेशोत्सव मंडल, पुलिस और मनपा प्रशासन के बीच बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा ने इस वर्ष भी गणेशोत्सव को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाने की अपील की है। आयुक्त ने गणेश मंडलों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह कुछ निर्देश दिए थे, जिसका पालन मनपा प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार मंडलों को निःशुल्क अनुमति दी जाएगी। आयुक्त ने मंडलों से गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का आह्वान करते हुए आश्वस्त किया कि विसर्जन रोड, सड़कों पर गड्ढों, ओवरहेड तार, जिन स्थानों पर पेड़ की शाखाएं गणेश विसर्जन मार्ग में बाधा डाल रही हैं, वहां की शाखाओं को काटने का काम किया जाएगा। उन्होंने गणेशोत्सव मंडलों से कोर्ट के फैसले के अनुसार ही गणेशोत्सव मनाने का आह्वान किया है। महानगरपालिका ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष भी वन विंडो योजना लागू की जाएगी। हालांकि गणेशोत्सव मंडलों की ओर से प्रशासन से मंडप की अनुमति व अन्य अनुमति समय से दिलाने की मांग की गई, जिसमें मुख्य रूप से आरती का समय बढ़ाया जाए, सड़कें गड्ढों से मुक्त करने, विसर्जन की समय-सीमा बढ़ाने और देर रात तक विसर्जन के दौरान मनुष्य बल बढ़ाने जैसे मांगों का समावेश है।

सरकार पर अजीत पवार का जोरदार हमला

मुंबई : विधिमंडल अधिवेशन और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने कल पत्रकार परिषद लेकर 'ईडी' (एकनाथ-देवेंद्र) सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ज्वलंत सवाल करते हुए कहा कि राज्य में बहुमत की सरकार होते हुए भी राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है?

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में अतिवृष्टि घोषित करने की मांग उन्होंने राज्य सरकार से की है। इसी के साथ राज्य में बहुमत की सरकार होते हुए भी अधिवेशन क्यों नहीं लिया जा रहा है। अधिवेशन लेने के लिए तुम्हें किसने रोका है? ऐसा सवाल उन्होंने शिंदे-फडणवीस सरकार से पूछा। राज्य में वर्तमान में अतिवृष्टि शुरू है। हमारे अनेक विधायकों ने अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण किया है। जनता की समस्याओं को विधिमंडल में उठाने का विधायकों को अधिकार है। जब अधिवेशन ही नहीं होगा तो वे सवाल कहां उठाएंगे? ऐसा सवाल उन्होंने पूछा। राज्य में अतिवृष्टि घोषित किया जाए, इसके लिए राज्य सरकार को उन्होंने पत्र लिखा है। जुलाई महीने में बांध भर गए हैं। विदर्भ, मराठावाड़ा में कई किसानों का नुकसान हुआ है। इसलिए राज्य में अतिवृष्टि घोषित करो, ऐसा पवार ने कहा।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैजल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नंबर 3-4, अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट, सोनावाला क्रॉस रोड नंबर 12, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई - 63 से छपवाकर रूम नंबर 15 रमजान बिन 17- सी, वंजावडी, माहिम (वेस्ट), मुंबई - 400016 से प्रकाशित किया . संपर्क कार्यालय 1 ए, ग्राउंड फ्लोर, साहिल मेन्शन, बालमिया लेन, माहिम (वेस्ट), मुंबई - 400016.
मोबाइल नंबर 9987775650 व्हाट्सएप नंबर 9987775650 ईमेल- editor@rokthoklekhaninews.com -किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मुंबई होगा!
www.rokthoklekaninews.com facebook@rokthoklekhani youtube@rokthoklekhani twitter@rokthoklekhani